

विकसित उत्तर प्रदेश 2047 : एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम की भूमिका

सुनील कुमार त्रिपाठी एवं संजीव रत्न

<https://doi.org/10.61410/had.v21i2.305>

सारांश :

भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं विविधता युक्त देश है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहां भारत की कुल जनसंख्या का 16.49 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हिस्सा निवास करता है। उत्तरांचल राज्य के गठन (8 नवम्बर 2008) के बाद अब उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी ही रह गया है, जो सम्पूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने हेतु मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में “एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम” की शुरुआत की। एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम 1979 ई0 में जापान द्वारा प्रारम्भ की गई, एक गाँव-एक उत्पाद (ओ0वी0ओ0पी0) की मूल अवधारणा पर आधारित है। इस योजना को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू किया गया है। भारत सरकार ने भी इस योजना से प्रभावित होकर इसे पूरे देश के सभी जनपदों में लागू करने की पहल की है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से बदलकर उनकी गुणवत्ता और मानकों में सुधार करना है, ताकि उत्पादक सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें तथा प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना है। ओ0डी0ओ0पी0 परियोजनाएँ छोटे उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना हैं तथा सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए प्रत्येक जिले से कम से कम एक उत्पाद का चयन ब्रांडिंग व प्रचारित करना है। यह व्यवसाय सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम की अम्ब्रेला योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश –2047 की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य राज्य को ट्रिलियन अर्थ व्यवस्था बनाना है।

इस योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राज्य के आर्थिक विकास में योगदान कर रहा है।

कुंजी शब्द —ओ0डी0ओ0पी0, स्थानीय उत्पाद, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, आर्थिक विकास,

अम्ब्रेला योजना।

प्रस्तावना :

उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। राष्ट्रीय योगदान के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। चाहे कुल जनसंख्या का सवाल हो या संसद में सांसदों की संख्या का इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वोपरि है। पिछले 75 वर्षों में 40से अधिक वर्षों तक इसी राज्य के लोग

-
- शोधार्थी सहायक आचार्य, अर्थ शास्त्र विभाग, राणा प्रताप पी0जी0 कालेज, सुलतानपुर।
 - शोध निर्देशक, सह आचार्य, अर्थ शास्त्र विभाग, संत तुलसीदास पी0जी0 कालेज, कादीपुर, सुलतानपुर।
-

प्रधानमंत्री होते आये है। सिर्फ राजनीति ही नहीं संस्कृति, इतिहास एवं सामाजिक, आर्थिक भौगोलिकता की दृष्टि से भी यह राज्य भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं कृषि प्रधान इस राज्य के कुल 2,40,928 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर 19,98,12,341 लोग निवास करते है, जिसमें 10.45 करोड़, पुरुष और 9.53 करोड़ महिलाएं है। इनमें से 67.7 प्रतिशत लोग साक्षर है। (स्रोत-उत्तर प्रदेश-2023)

“विकसित उत्तर प्रदेश 2047” मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य को भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक 6 ट्रिलियन डालर की अर्थ व्यवस्था और एक समृद्ध, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समावेशी प्रदेश बनाने का एक रणनीतिक विजन है, इसका लक्ष्य 2047 तक प्रति व्यक्ति आय को ₹0 26 लाख प्रति वर्ष करना, विश्व स्तरीय आधार भूत ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और डिजिटल सेवाओं का विकास करना है।

यह विजन 2047 एक ऐसा रोड मैप है जो उत्तर प्रदेश को आत्म निर्भर, समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने का लक्ष्य रखता है। बिना उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाये भारत को 2047 तक विकसित देश नहीं बनाया जा सकता है।

आज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बन कर उभरी है, जिसने तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0)में लगभग 8 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है, जो इसे 2027 तक भारत की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था वाला राज्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त कराना हैं 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था देश में छठवें व सातवें स्थान पर थी तथा इस प्रदेश को बीमारू राज्य की संज्ञा से विभूषित किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश तीव्र विकास के कारण दूसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बनकर उभरी है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के मामले में भारत का दूसरा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला राज्य बन गया है, जिसकी विकास दर 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गयी है। वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का जी0एस0डी0पी0 25.48 लाख करोड़ रुपया रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 22.58 लाख करोड़ था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2029 तक 1 ट्रिलियन डालर की अर्थ व्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें कानून और व्यवस्था, कृषि, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, तकनीकी उन्नयन, शून्य गरीबी एवं अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा किफायती एवं व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ तथा रोजगार के साथ सौ प्रतिशत कुशल श्रमिक शामिल किये जायेंगे।

विकसित उत्तर प्रदेश डायलॉग को महिलाओं, युवाओं, किसानों और वंचितों के समावेशी विकास पर केन्द्रित किया जायेगा। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में नोडल अधिकारी और प्रबुद्ध जन आम जनता से संवाद स्थापित करके विकसित उत्तर प्रदेश का रोड मैप तैयार करने में सहयोग कर रहे है। इसमें प्रदेश की विकास यात्रा और भविष्य की रूप रेखा पर चर्चा के लिए ग्रामीण लोगों ने विशेष अभिरुचि दिखाई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, नगरीय एवं ग्रामीण विकास, आईटी प्रौद्योगिकी और उद्योग जैसे क्षेत्रों पर जनता का ज्यादा जोर दिखाई दिया।

राज्य सरकार जनता के इन सुझावों को विकास रोड मैप में शामिल कर उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने में ठोस कदम उठायेगी।

विकसित उत्तर प्रदेश एवं एक जिला-एक उत्पाद योजना-

एक जिला-एक उत्पाद कार्यक्रम विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो राज्य के आर्थिक विकास में योगदान कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य 2047 तक उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को 6 ट्रिलियन डालर तक पहुंचाना है। इसके माध्यम उत्तर प्रदेश सभी 75 जनपदों में उत्पाद विशिष्ट एवं स्थानीय पारस्परिक विनिर्माण केन्द्र की स्थापना गई है। इससे राज्य के सभी जिलों में पारस्परिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने इस योजना की प्रशंसा करते हुए बताया कि यह योजना सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागू की जानी चाहिए, जो कि मेक इन इंडिया के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों में आत्म निर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करेगी। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक युवा आबादी के साथ-साथ असीम सम्भावनाओं की भूमि है। कृषि अर्थ व्यवस्था, बड़े उपभोक्ता बाजार एवं बड़ी आबादी वाले स्थान को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, परन्तु पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिलब्ध काफी बदल गया है। राज्य की अर्थ व्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गयी है। राज्य की निवेशक सम्मेलनों ने निवेश के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

निवेशको के विश्वास ने उत्तर प्रदेश ने 15 लाख करोड़ से अधिक का निवेश भौतिक रूप से जमीन पर आकार प्रदान कर दिया है।

वर्ष 2016-17 में राज्य की अर्थ व्यवस्था (जी0एस0डी0पी0) 13.30 लाख करोड़ रुपये थे, जो वर्ष 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुकी है, अब इसके 36 लाख करोड़ पर पहुंचने का अनुमान है। पिछले नौ वर्षों में (2017-2026) प्रदेश के औद्योगिक विकास ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवधि में 17,841 से अधिक नये कारखाने पंजीकृत हुए, जिससे कुछ पंजीकृत उद्योगों की संख्या-32 हजार के ऊपर पहुंच चुकी है। (इन्वेस्ट यूपी)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम , भारतीय अर्थ व्यवस्था को शीर्ष की ओर अग्रसर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है। ये उद्यम बाजार के अनुसार कम लागत में अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराता है। इसके साथ-साथ ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करते हुए संतुलित विकास, राष्ट्रीय आय एवं क्षेत्रीय समृद्धि का न्यायसंगत वितरण की दिशा में पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करता है।

उद्यम पोर्टल के अनुसार-एम0एस0एम0ई0 दो करोड़ से अधिक रोजगार प्रदान करने के साथ स्वयं को अर्थ व्यवस्था की आधारशिला के रूप में स्थापित करता है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत 20.51 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, जो उद्यम पंजीकृत एम0एस0एम0ई0 द्वारा सृजित कुल रोजगार का 18.73 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिसमें से 89.64 लाख इकाइयाँ सूक्ष्म उद्यम एवं .36 लाख इकाइयाँ लघु उद्यम में हैं, जो कि 1.4 करोड़ से अधिक लोगों को

रोजगार प्रदान करती है तथा अनेक एम0एस0एम0ई0 की निर्यातनुमुखी प्रवृत्ति ने प्रदेश की विदेशी मुद्रा आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र से निर्यात मूल्य लगभग 16 बिलियन डालर था, जो कि प्रदेश के कुल निर्यात का लगभग 70 प्रतिशत था।

उत्तर प्रदेश ने ब्रांडिंग, विपणन एवं प्रोत्साहन में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार ने प्रमोटिंग लीडरशिप एण्ड इन्टरप्राइजेज फार डेवलपमेंट आफ ग्रोथ इंजन (प्लेज) योजना प्रारम्भ की है, जो निजी उद्यमों को प्रदेश में औद्योगिक पार्क विकसित करने का अवसर देती है, जिससे ये प्रदेश की आर्थिक सफलता की महत्वपूर्ण कड़ी बन गये हैं। राज्य के निर्यात में एम0एस0एम0ई0 इकाइयों का योगदान 45 प्रतिशत है।

प्रदेश सरकार के विजन डोक्यूमेंट के अनुसार लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा को वैश्विक पहचान दिलाकर प्रतिस्पर्धी शहर के रूप में विकसित किया जायेगा इन शहरों में आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत ढांचा को वैश्विक आकार प्रदान करने, ओडीडीपी0 का विस्तार करने का अवसर उपलब्ध रहेगा। इससे एक्सप्रेस-वे नेटवर्क में क्रांति आयेगी, जिससे कि व्यापारिक सम्पर्क, निवेश को आकर्षित करने एवं यातायात को सुगम बनाने में आसानी होगी।

विकसित उत्तर प्रदेश 2047 योजना में पर्यावरण संरक्षण को विशेष प्राथमिकता प्रदान की गई है। वर्तमान में राज्य में 8.82 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है, जिसे 2030 तक 14 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

एक जिला-एक उत्पाद, उ0प्र0 के सभी 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट परम्परागत विनिर्माण केन्द्र को स्थापित करते हुए स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाते हुए विशिष्ट निर्यात क्षेत्र की स्थापना करना है।

सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उपक्रम की भूमिका-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम, भारतीय अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है। ये उद्यम कम लागत एवं पूंजी के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करते हैं, तथा दूसरी तरफ देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में सहायता करते हैं। इससे क्षेत्रीय असंतुलन में कमी आती है तथा आय का समान वितरण सुनिश्चित होता है। आज पूरी दुनिया में 70 प्रतिशत रोजगार में एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र का योगदान है। देश में सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात तथा रोजगार सृजन में इसका योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। सम्पूर्ण भारत में, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार की तीसरी औद्योगिकी नीति 1977 में राज्य सरकार के अधीन जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गई थी। इस समय देश में एम0एस0एम0ई0 की सभी योजनाएं जिला उद्योग, उद्यम प्रोत्साहन एवं निर्यात केन्द्र द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। एक जुलाई 2020 से नये एवं विद्यमान उद्यमों के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन नामक नया पोर्टल विकसित किया गया है, जो कि ऑनलाइन एवं निःशुल्क है। अब तक 20 लाख से अधिक उद्यमी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कोरोना संकट का मुकाबला करने के लिए “आत्म निर्भर भारत” अभियान के अन्तर्गत एम0एस0एम0ई0 में कई कार्यक्रम चलाये गये हैं, जिसमें इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम (ई0सी0एल0जी0एस0) प्रमुख है। इसमें उद्यम प्रोत्साहन के लिए गारण्टी और कोलेटरल फ्री लोन दिये जाते हैं। वोकल फार लोकल

की नई विचार धारा ने ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर भारतीय अर्थ व्यवस्था को आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था के साथ-साथ स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को गतिमान कर दिया है।

स्टार्टअप इंडिया :

भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी के कर कमलो से यह योजना प्रारम्भ की गई थी। इसके माध्यम से नये उद्यमियों एवं युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके द्वारा सरकार नव प्रवर्तन एवं नये विचारों वाले व्यवसायों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता टैक्स छूट एवं गारन्टी युक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है।

मेक इन इंडिया-

इस योजना को भारत सरकार द्वारा देश की अर्थ व्यवस्था को आत्म निर्भर बनाने के लिए 25 सितम्बर 2014 को प्रारम्भ की गई थी। इसके माध्यम से देश में स्वदेशी उत्पादों एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए युवाओं के लिए बहुआयामी रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। ग्रामीण स्त्रियों को आत्म निर्भर करने में सरकार की भूमिका कई स्तरों पर है। महिलाओं को जहां एक तरफ आर्थिक सहायता और समर्थन की जरूरत है, वही शिक्षण –प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसके तहत कई तरह की योजनाएं हैं-

दीन दयाल अन्त्योदय योजना-इस योजना में बैंकों से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 3 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को ब्याज सहायता देने का प्रावधान है।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एम0के0एस0पी0)

स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एस0जी0ई0पी0)-2016

स्टैण्डअप इंडिया ऋण योजना-5 अप्रैल 2016

राष्ट्रीय महिला कोष-1993

स्टेप (स्पोर्ट फार ट्रेनिंग एण्ड एम्प्लायमेन्ट प्रोग्राम फार वीमैन)

ग्रामीण महिला टेक्नोलॉजी पार्क (आर0डब्ल्यू0टी0पी0)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी0एम0एम0वाई0)-8 अप्रैल 2015

एम0एस0एम0ई0 की प्रगति-

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कराये गये 73वें चक्र के अनुसार देश में वर्ष 2015-16 में 633.88 लाख गैर नियमित तथा गैर कृषि आधारित इकाइयाँ थी जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थी। सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम लघु आकार के तथा 0.17 प्रतिशत मध्यम आकार के हैं। 45 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 55 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में हैं। इसमें से 67.17 प्रतिशत उद्योग विनिर्माण क्षेत्र में, 16.78 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में तथा 16.13 प्रतिशत टूट फूट की मरम्मत तथा अनुरक्षण के क्षेत्र में हैं।

स्रोत-भारत-2023

अखिल भारतीय उद्यमों का वितरण (संख्या लाख में)

	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
भारत	630.52	3.31	.05	633.88
उत्तर प्रदेश	89.64	.36	.03	90.03

स्रोत (केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय)

निष्कर्ष एवं सुझाव :

भारतीय स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष पूर्ण करने के समय भारत को आत्म निर्भर एवं विकसित भारत बनाने का महत्वाकांक्षी संकल्प लिया गया है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था वाला राज्य बन गया है। 2047 तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया है। इसे साकार करने के लिए प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला ओ0टी0डी0 सेल का गठन किया गया है। इसमें उ0प्र0 की अर्थ व्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर के स्तर तक लाये जाने हेतु प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किया जा रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निवेश संवर्धन, अवस्थापना सुविधाओं का विकास पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा, विशेष निवेश क्षेत्र की स्थापना, विनिर्माण, आई0टी0, स्टार्टअप और कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं “एक जिला-एक उत्पादन” कार्यक्रम आदि विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी प्रयास किये जा रहे हैं।

इस लक्ष्य की प्राप्ति में एक जिला-एक उत्पाद योजना विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के संकल्प का एक मुख्य आधार स्तम्भ होगी। इससे ग्रामीण युवाओं और शिल्पकारों को अपने जनपद में स्थानीय रोजगार मिलेगा तथा स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी। 2047 तक उत्तर प्रदेश में लाखों नये रोजगार और स्टार्टअप ओ0डी0ओ0पी0 योजना से जुड़कर उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में अहम भूमिका निभायेंगे। इन उत्पादों को जी0आई0 टैग, गुणवत्ता प्रमाणन और ई-कामर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को ब्रांड यूपी के रूप में पहचान दी जायेगी। इससे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक पहचान एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कच्चे माल की स्थानीय आपूर्ति, पैकेजिंग, लाजिस्टिक और विपणन का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा होगा। इससे ग्रामीण आय को दोगुना करने के साथ-साथ रिवर्स माइग्रेशन बढ़ेगा।

सन्दर्भ सूची-

- 1- इन्वेस्ट यूपी0
- 2- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।
- 3- कुरुक्षेत्र फरवरी 2021
- 4- योजना मार्च 2021
- 5- उत्तर प्रदेश वार्षिकी 2022 : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0।
- 6- उ0प्र0 विजन डोक्यूमेन्ट।
- 7- एल0एन0 कोली/के0 कुमार- भारतीय अर्थ व्यवस्था एवं उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था।
- 8- उ0प्र0 का बजट 2023-24 एक दृष्टि।
- 9- भारत-2023